

Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on ?Demands for Grants (2025-2026)? pertaining to the Department of Consumer Affairs of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution-Laid

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 7 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

12.09½ hrs